

मुकदमों का विवरण

फुलमती धर्मदेव यादव और ए. एन. आर. बनाम

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी लिमिटेड. और ए. एन. आर. (2023 की सिविल अपील संख्या 4713)

सितंबर 04, 2023

[अभय एस. ओका और संजय करोल, जेजे।] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय का आदेश मृतक कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में मुआवजा देने वाले आयुक्त के आदेश अपास्त करते हुए करता है।

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923-पीड़ित की मृत्यु हो गई क्योंकि वह ट्रेलर पर लॉग बांध रहा था-आयुक्त ने बीमाकर्ता को ₹ 3,94,120 का मुआवजा देने का निर्देश दिया-और नियोक्ता को ₹ 1,97,060 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया-यानी मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत जुर्माना के रूप में-उच्च न्यायालय ने आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: आक्षेपित निर्णय के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय अनुज्ञात विधि के किसी भी ठोस प्रश्न को तैयार नहीं किया-अधिनियम के शब्दों से संकेत मिलता है कि इस तरह के प्रश्न का अस्तित्व अपील पर विचार कर अनुज्ञात के लिए एक पूर्व शर्त है-दो निर्णयों के बीच अंतर, यानी, आयुक्त का आदेश और प्रथम अपील में निर्णय, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित हो अनुज्ञात के बिंदु पर था-आयुक्त अनुज्ञात ऐसा संबंध स्थापित किया था, हालांकि, अपील अदालत अनुज्ञात कहा कि "दावेदार इस पहलू को साबित कर अनुज्ञात में स्पष्ट विरचित से विफल रहे हैं"-आयुक्त अनुज्ञात मृतक के लाइसेंस की अनुपलब्धता की वैधता के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया था और न ही यह आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों में से एक था।

374

फुलमती धर्मदेव यादव और ए. एन. आर. बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

नियोक्ता कंपनी के इस पर्यवेक्षक की; और जांच पंचनामा प्रपत्र में उल्लिखित विवरण, जब एक साथ विचार किया जाता है, तो मृतक व्यक्ति के नियोक्ता की सूची में होने के पहलू की ओर इशारा करता है-सामाजिक कल्याण और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए; तथ्यों पर आयुक्त अंतिम प्राधिकारी है; उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपील का दायरा केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों तक सीमित है;

और आयुक्त के आदेश से कोई विकृति प्रदर्शित नहीं की जा सकती है।[पारस 18,19,21,22,29,32]

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, **1923 -एस. 30-**एक आदेश आयुक्त की अपील-यदि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए:

आयोजित किया गया:अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आयुक्त के आदेश की अपील पर तभी विचार किया जा सकता है जब विचार करने के लिए विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद हो-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि इस अधिनियम के भीतर "विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न " वाक्यांश को इसके सामान्य अर्थ से समझा जाएगा-जब इस वाक्यांश के सामान्य अर्थ पर विचार किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से, संदर्भ सिविल प्रक्रिया संहिता के लिए होता है-इसमें नियम यह है कि विधि के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करना महत्वपूर्ण महत्व का है।[पैरा 17]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

उत्तर-पूर्वी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम बनाम सुजाता (2019) 11 एससीसी 514:
[2018] 13 एस. सी. आर. 1043; सी. मंजम्मा बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2022) 6 एस. सी. सी. 206; के. शिवरामन बनाम पी. सतीश कुमार (2020) 4 एस. सी. सी.

594 :[2020] 4 एस. सी. आर. 480-निर्भर।ओम प्रकाश बातिश बनाम रंजीत (2008) 12 एस. सी. सी. 212:[2008] 6 एससीआर 938;

गोल्ला राजम्मा और ओआरएस बनामसंभागीय प्रबंधक और ए. एन. आर. (2017) 1 एससीसी 45:

[2016] 9 एस. सी. आर. 469-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील सं. 4713।2013 के एफ. ए. No.3487 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.02.2019 के निर्णय और आदेश से।

376 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

रूप:

श्रेयस मेहरोत्रा, सुश्री सविता सिन्हा, राहुल गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

डॉ. मीरा अग्रवाल, रमेश चंद्र मिश्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय
का
निर्णय/आदेश
निर्णय

संजय करोल जे.,

1. यह अपील 2013 की पहली अपील में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले पर आरोप लगाते हुए फुलमती धर्मदेव यादव के कहने पर की गई है, जिसमें न्यायालय ने कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, भुज (कच्छ), गुजरात के आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया है।
2. यहाँ 1 में अपीलकर्ता रमाकांत यादव 2 की माँ और पत्नी हैं, जिनकी कथित रूप से 31 अक्टूबर, 2009 को मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वे ट्रेलर पर लॉग बांध रहे थे, जब वे इसके चालक के रूप में काम कर रहे थे, जब ऐसा ही एक लॉग उनके बाएं पैर पर गिर गया था। इलाज होने से पहले ही उनकी मौत हो गई।
3. कथित तौर पर मृतक कच्छ कैरियर (सोहान्सिंग एंड संस 3) का कर्मचारी था, जिसे 4000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता था।
4. बीमाकर्ता द्वारा रोजगार के दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण मृतक के इस तरह के रोजगार से इनकार कर दिया गया था। न ही मृतक की आय का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
5. ₹ 3,94,120-के दावे को बीमाकर्ता-उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त शर्तों में अस्वीकार कर दिया गया है।

आयुक्त का आदेश

6. दावे के अस्वीकार से व्यथित महसूस करते हुए, कार्यवाही की गई

1 इसके बाद "दावेदार" के रूप में संदर्भित 2 इसके बाद "मृतक" के रूप में संदर्भित

3 इसके बाद "नियोक्ता" के रूप में संदर्भित किया जाता है। आयुक्त 377 के समक्ष विरोधी 1

फुलमती धर्मदेव यादव और ए. एन. आर. बनाम न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड. और ए. एन. आर. [संजय करोल जे.] 378 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

आयुक्त, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, भुज (कच्छ), गुजरात के समक्ष दावेदारों द्वारा W.C.F.C.No.08/10 के संदर्भ में शुरू किया गया। आयुक्त ने विचार के लिए 8 मुद्दे विरचित किए। नीचे दी गई सारणीबद्ध प्रस्तुति विरचित किए गए मुद्दों, उन पर तर्क और वापस किए गए तथ्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

एस. नहीं	मुद्दा	आदेश दें	तर्क करना
1	मृतक के उत्तराधिकारी और आश्रित कौन हैं?	भावनात्मक रूप से	दावेदार मृतक आश्रित हैं।
/	क्या मृतक नियोक्ता का कर्मचारी था?	भावनात्मक रूप से	प्रश्न एफ़. आई. आर. में मृतक का नाम नियोक्ता के कर्तव्य का पालन करने वाले चालक के रूप में सामने आया है।

3. डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर ए सी आई डी एन टी

संबद्ध कोई दस्तावेज़ इसके विपरीत नहीं है

पाठ्यक्रम के दौरान हुआ

नियोक्ता द्वारा दिखाया गया।

रोजगार का? यदि हां, तो

तब मृतक की मृत्यु हो गई क्योंकि

दुर्घटना में चोटें?

/	दुर्घटना के समय उम्र साबित होती है या नहीं? और ₹4,000/- की मासिक आय साबित होती है?	3 5 वेतन ₹4,000/-	ड्राइविंग लाइसेंस द्वारा आयु निर्धारित की जाती है जिसमें जन्म तिथि 01-05-74 दर्शाई जाती है। बीमाकर्ता द्वारा कोई प्रतिकूल साक्ष्य नहीं दिखाया गया है। वेतन ₹4,000/- प्रति माह होने पर पूर्व-19 के
---	--	-------------------	---

			बयान पर निर्भरता रखी गई थी।
/	क्या विरोधी मुआवजे की राशि के लिए उत्तरदायी हैं? यदि हां, तो कितनी राशि?	भावनात्मक रूप से	₹ 3,94,120 का मुआवजा दिया गया-इस आधार पर कि मृतक की मृत्यु पाठ्यक्रम के दौरान हुई थी और दावेदार द्वारा रखे गए दस्तावेजों के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा एक एस. ओ. डब्ल्यू. एन. ई. आर. एस. एच. आई. पी. यू. सी. के. का भी बीमा किया गया था।

/	बीमा कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? ?	भावनात्मक रूप से	मृतक वाहन संख्या पर नियोक्ता के साथ चालक के रूप में कार्यरत था। जीजे-12 डब्ल्यू7670। वाहन का बीमा होने के कारण, बीमाकर्ता को दुर्घटना की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना था।
7	मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है? यदि हां, तो क्या वे जुर्माना और ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं?	भावनात्मक रूप से	नियोक्ता ने दुर्घटना की जानकारी होने के दौरान कार्य और क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर दावेदार को मुआवजे का भुगतान नहीं किया, इसलिए 50 प्रतिशत की

			दर से जुर्माना लगाया गया।
।	फि नाल ऑर्डर क्या है?	भावनात्मक रूप से	₹3000/- खर्च के लिए और दावेदार को अंतिम संस्कार के खर्च के लिए ₹5,000/- का भुगतान किया जाना है।

7. उपरोक्त के संदर्भ में, बीमाकर्ता-न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4 को मृतक की मृत्यु की तारीख से उपार्जित ब्याज के साथ मुआवजे के रूप में ₹ 3,94,120 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। आदेश के 30 दिनों के भीतर उसी का भुगतान किया जाना था। नियोक्ता को जुर्माना के रूप में ₹ 1,97,060-यानी मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, यह निर्देश दिया गया था कि बाद वाला विशेष रूप से खर्च और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए ₹8,000/- (₹3,000/- और ₹5,000/- के विभाजन के साथ) का भुगतान करेगा।

8. केवल बीमाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ अपील की।

प्रथम अपील-आक्षेपित निर्णय

9. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पहली अपील के लंबित रहने के दौरान, 2013 के सिविल आवेदन संख्या 2822 में पारित 25 जून, 2014 के एक आदेश के माध्यम से आयुक्त को उस राशि का 80 प्रतिशत निवेश करने का निर्देश दिया गया था जो

4 इसके बाद "बीमाकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाता है

379

फुलमती धर्मदेव यादव और ए. एन. आर. बनाम न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड. और ए. एन. आर. [संजय करोल जे.] 380

तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए संचयी जमा में ऐसे प्राधिकरण के पास जमा किया जाता है, जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता है और शेष 20 प्रतिशत दावेदारों को वितरित किया जाता है।

10. अभिलेख पर साक्ष्य जैसे कि गांधीग्राम "ए" डिवीजन पुलिस स्टेशन के आकस्मिक मृत्यु रजिस्टर का सार, और दावेदार यानी मृतक की पत्नी से जिरह के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, विद्वान न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक न तो नियोक्ता के साथ काम कर रहा था और न ही घटना की घटना की तारीख को, उसे चोटें आईं और उसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। 11. इसलिए आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

12. इस प्रकार, वर्तमान अपील।

13. विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से अन्य आधारों के साथ यह भी आग्रह किया गया है कि प्रथम अपील में न्यायालय ने श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 30 की शर्तों का उल्लंघन किया है; जिस वाहन में लट्टों को संग्रहीत किया गया था और इस तरह से खोला जा रहा था, उसका बीमा किया गया था और इसलिए, दुर्घटना बीमा कंपनी की जिम्मेदारियों के दायरे में है; कि आक्षेपित निर्णय ने दावेदारों को उपचारहीन और बिना किसी समर्थन के छोड़ दिया है क्योंकि परिवार के एकमात्र कमाने वाले का निधन हो गया था।

विक्षेपण और विचार

14. वर्तमान विवाद को नियंत्रित करने वाले अधिनियम, अर्थात् श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 को श्रमिक मुआवजा (संशोधन) अधिनियम, 2009 के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसके द्वारा "कर्मचारी" शब्द को "कर्मचारी" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिसे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

15. इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आक्षेपित निर्णय कानूनी रूप से पोषणीय है? गुण-दोष के आधार पर यह विचार किया जाएगा कि अभिलेख में दी गई सामग्री के आलोक में आयुक्त का आदेश कायम रह सकता है या नहीं? दूसरे शब्दों में, आक्षेपित निर्णय दो आधारों पर सही होना चाहिए, (i) वैधानिक पाठ; और (ii) क्या अभिलेख पर सामग्री उसमें निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन करती है या नहीं?

5 इसके बाद, अधिनियम

/

[2023] 14 एस सी आर।

16. अधिनियम के भीतर अपील धारा 30 द्वारा शासित होती है जो संदर्भ के लिए नीचे दी गई है:—

“30. अपील करते हैं।— (1) एक आयुक्त के निम्नलिखित आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, अर्थात्:—

क्षतिपूर्ति के रूप में एकमुश्त राशि प्रदान करने का आदेश, चाहे वह आधे मासिक भुगतान के मोचन के रूप में हो या अन्यथा या एकमुश्त के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से दावे की अनुमति न देना हो।

1 [(ए) धारा 4 ए के अंतर्गत ब्याज या जुर्माना देने का आदेश; (बी) अर्ध-मासिक भुगतान के मोचन की अनुमति देने से इनकार करने वाला आदेश; (सी) मृतक के आश्रितों के बीच मुआवजे के वितरण का प्रावधान करने वाला आदेश [कर्मचारी], या किसी ऐसे व्यक्ति के किसी भी दावे की अनुमति नहीं देता है जो खुद को ऐसा आश्रित होने का आरोप लगाता है;

(घ) धारा 12 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि के लिए किसी भी दावे को अनुमति देने या अस्वीकार करने वाला आदेश; या (ङ) समझौते के ज्ञापन को पंजीकृत करने से इनकार करने या उसे पंजीकृत करने या शर्तों के अधीन उसी के पंजीकरण के लिए प्रावधान करने वाला आदेश:

बशर्ते कि किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि अपील में विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल न हो और खंड (बी) में निर्दिष्ट आदेश के अलावा किसी अन्य आदेश के मामले में, जब तक कि अपील में विवादित राशि 2 रुपये से कम न हो [दस हजार रुपये या ऐसी अधिक राशि जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे]:

बशर्ते कि किसी भी मामले में कोई अपील नहीं होगी जिसमें पक्षकार आयुक्त के निर्णय का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं, या जिसमें आयुक्त का आदेश पक्षकारों द्वारा किए गए समझौते को प्रभावी बनाता है:

3 [बशर्ते कि खंड (ए) के अंतर्गत किसी नियोक्ता द्वारा कोई अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि अपील के ज्ञापन के साथ आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि अपीलकर्ता ने उसके साथ उस आदेश के अंतर्गत देय राशि जमा कर दी है जिसके खिलाफ अपील की गई है।

फुलमती धर्मदेव यादव और ए. एन. आर. बनाम न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड. और ए. एन. आर. [संजय करोल जे.] 382

(2) इस धारा के अंतर्गत अपील के लिए सीमा की अवधि साठ दिन होगी।

(3) 4 की धारा 5 [भारतीय सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)] के प्रावधान इस धारा के अंतर्गत अपीलों पर लागू होंगे।" (जोर दिया गया) 17. अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आयुक्त के आदेश की अपील पर तभी विचार किया जा सकता है जब विचार करने के लिए विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद हो। इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि इस अधिनियम के भीतर "कानून का सारवान प्रश्न" वाक्यांश को इसके सामान्य अर्थ से समझा जाएगा।¹⁶ इस वाक्यांश के सामान्य अर्थ पर विचार करते समय, स्वाभाविक रूप से, संदर्भ सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) के लिए है। उसमें नियम यह है कि विधि के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करना महत्वपूर्ण है।

18. आक्षेपित फैसले के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि न्यायालय ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनाया था।

19. अधिनियम के शब्दों से संकेत मिलता है कि इस तरह के प्रश्न का अस्तित्व अपील पर विचार करने के लिए एक पूर्व शर्त है।

20. सचित्र रूप से, उत्तर-पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन में

निगम बनाम सुजाता 7 (दो-न्यायाधीशों की पीठ) कई अन्य मामलों के बीच, इस न्यायालय ने कहा है:

“12. दूसरे शब्दों में, आयुक्त के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दी गई अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के समान एक नियमित पहली अपील की तरह नहीं है, जिस पर तथ्यों और विधि दोनों पर सुनवाई की जा सकती है। अपील पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता केवल मामले में उत्पन्न होने वाले विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जांच करने के लिए है। ”

21. दूसरा आधार जो आदेश को चुनौती के अंतर्गत बनाता है, हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी है जब अधिकार क्षेत्र का दायरा केवल "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न " के मामलों में प्रयोग किया जा रहा है, वह आदेश में विकृति है। यहाँ, आक्षेपित निर्णय, यहाँ तक कि दूर से भी नहीं,

6 ओम प्रकाश बातिश बनाम रंजीत (2008) 12 एस. सी. सी. 212 (2 न्यायाधीश-पीठ) 7 (2019) 11 एस. सी. सी. 514

/

[2023] 14 एस सी आर।

इस अवलोकन को प्रतिबिंबित करें कि आयुक्त द्वारा किए गए निर्णय विकृत हैं। दोनों निर्णयों, अर्थात् आयुक्त के आदेश और प्रथम अपील में निर्णय के बीच अंतर नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित होने के बिंदु पर था। आयुक्त ने माना कि इस तरह का संबंध स्थापित किया गया है, हालांकि अपील न्यायालय ने कहा कि "दावेदार इस पहलू को साबित करने में स्पष्ट रूप से विफल रहे हैं"

22. यहां केवल यह ध्यान दिया जा सकता है कि आयुक्त ने मृतक के लाइसेंस की अनुपलब्धता की वैधता के संबंध में कोई आवेदन वापस नहीं किया था और न ही यह आयुक्त द्वारा विचार के लिए विरचित गए प्रश्नों में से एक था। ऐसी स्थिति में, अधिनियम की धारा 30 द्वारा अनुज्ञात सीमित दायरे के भीतर शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय ने टिप्पणियाँ करने और उस संबंध में एक धारणा देने में गलती की।

23. इस न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि आयुक्त किसी मामले में शामिल तथ्यों पर अंतिम प्राधिकारी होता है। गोल्ला राजम्मा और ओआरएस बनाम संभागीय प्रबंधक और ए. एन. आर. 8 (2-न्यायाधीश पीठ) यह पाया गया कि "अधिनियम की योजना के तहत, कामगार मुआवजा आयुक्त तथ्यों पर अंतिम प्राधिकारी है। संसद ने सोचा है कि यह अपील का दायरा केवल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह एक कल्याणकारी विधि है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय सीमित अधिकार क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण प्रश्न से चूक गया है और साक्ष्य की पुनः सराहना करने का प्रयास किया है और अक्षमता के प्रतिशत पर अपने स्वयं के निर्णय दर्ज किए हैं, जिसका भी कोई आधार नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा की

गई पूरी कवायद अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की क्षमता के भीतर नहीं है।

24. उक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित निर्णय, पूर्व-दृष्टि, इसके उल्लंघन में प्रतीत होता है।

25. गुण-दोष पर भी, हम मानते हैं कि आयुक्त द्वारा लिए गए निष्कर्ष निस्संदेह "एक संभावित दृष्टिकोण" थे, इसलिए तथ्यों में विकृति की संभावना को समाप्त कर देते हैं।

26. दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने सी. मंजम्मा बनाम न्यू में टिप्पणी की

इंडिया एस्योरेंस कं. लिमिटेड **9**

8 (2017) 1 एससीसी 45 9 (2022) 6 एससीसी 206 383

फुलमती धर्मदेव यादव और ए. एन. आर. बनाम.न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड. और ए. एन. आर. [संजय करोल जे.] 384

“15. यह स्थिति होने के कारण, आयुक्त द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में मामले का एक संभावित दृष्टिकोण था; और उच्च न्यायालय के लिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था, विशेष रूप से जब मामले में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1933 की धारा 30 के अर्थ के भीतर विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था। ”

27. आयुक्त के समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से, जैसा कि आदेश में वर्णित है, यह निश्चित रूप से एक असंभव, बहुत कम असंभव, निष्कर्ष नहीं होगा कि मृतक नियोक्ता के वेतन-सूची पर था। प्रथम दृष्टया, जो प्रश्न उठता है और पूरे समय अनुत्तरित रहता है, वह यह था कि मृतक ट्रॉली के साथ क्या कर रहा था और उस पर लदे सामान को भी, जिसे वह अपनी मृत्यु के समय बांध रहा था या खोल रहा था। दूसरा, आयुक्त के समक्ष रखे गए शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक नियोक्ता का कर्मचारी था। आयुक्त द्वारा दूसरे मुद्दे पर विचार करते हुए यह नोट किया गया है कि न तो कोई लिखित बयान दिया गया था और न ही नियोक्ता द्वारा आवेदकों के बयान को चुनौती दी गई थी; और भले ही उत्तरदाताओं ने याचिका में बताए गए तथ्यों का खंडन किया था और आवेदकों की जिरह की थी, लेकिन दावा याचिका की सामग्री का खंडन करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा कोई प्रतिकूल तथ्य साबित नहीं हुए और न ही कोई प्रतिकूल दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था।

28. इसके अतिरिक्त, अभिलेख को देखने के बाद हमें पता चला कि घटना स्थल 10 के पंचनामे में, यह दर्ज किया गया है कि घटनास्थल पर केवल एक व्यक्ति मौजूद था। वे सुनीलभाई रामजीभाई अहीर थे और नियोक्ता की कंपनी में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे। इन्क्वेस्ट पंचनामा फॉर्म 11 में नियोक्ता कंपनी का भी नाम है। उल्लिखित पता, जिसके साथ

मृतक जुड़ा हुआ था और वह व्यक्ति जिसने मृतक के शव की पहचान की है, उन दोनों के लिए यह नियोक्ता कंपनी के पते से मेल खाता है।

29. परिस्थितिसभ, अर्थात्, घटनास्थल पर मृतक की उपस्थिति; टॉली और उसमें लदे माल का स्वामित्व; नियोक्ता कंपनी के इस पर्यवेक्षक की उपस्थिति; और विवरण में उल्लिखित

10 पृष्ठ 23 पर अनुलग्नक पी-1

11 अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने के लिए आवेदन के पृष्ठ 9 पर अनुलग्नक पी-6

/

[2023] 14 एस सी आर।

पंचनामा प्रपत्र की जांच, जब एक साथ विचार किया जाता है, तो मृतक व्यक्ति के नियोक्ता की सूची में होने के पहलू की ओर इशारा करता है।

30. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यह अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है और इसलिए, इसे एक लाभकारी संरचना दी जानी चाहिए। इसके तहत मामलों का निर्णय विधि की उचित प्रक्रिया के साथ और अधिनियम के दायरे और इरादे के बारे में गहरी जागरूकता के साथ किया जाना है। इस न्यायालय ने बार-बार इस बात को दोहराया है

सिद्धांत। हम के. शिवरामन बनाम पी. सतीश कुमार **12** का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें, न्यायालय की ओर से बोलते हुए, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ जे. ने कहा:— “25. 1923 का अधिनियम एक सामाजिक लाभकारी विधान है और इसके प्रावधानों और संशोधनों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि कर्मचारी कानून के लाभ से वंचित न रहें। इस अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य आर्थिक रूप से गरीब कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करना था, जो काम में जोखिम या व्यावसायिक खतरों का सामना कर रहे थे, उन्हें आर्थिक लाभ के साथ क्षतिपूर्ति करने के लिए एक सस्ती और तेज मशीनरी प्रदान करना था। 1923 के अधिनियम में संशोधन इस मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए या तो मुआवजे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके या कर्मचारी को देय मुआवजे की राशि को बढ़ाकर अधिनियमित किया गया है। ”

(जोर दिया गया) 31। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आयुक्त ने मृतक के लाइसेंस की वैधता या अयोग्यता के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया था और न ही यह आयुक्त द्वारा विचार के लिए विरचित गए प्रश्नों में से एक था। ऐसी स्थिति में, अधिनियम की धारा 30 द्वारा अनुज्ञात सीमित दायरे के भीतर शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय ने टिप्पणियां करने और उस संबंध में एक धारणा देने में गलती की।

32. तथ्यों में, नियोक्ता कंपनी में मृतक के रोजगार की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों के संचयी योग के साथ; सामाजिक कल्याण और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए

कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए; आयुक्त तथ्यों पर अंतिम प्राधिकारी है; उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपील का दायरा केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों तक सीमित है; और कोई विकृति प्रदर्शित नहीं की जा सकती है।

12 (2020) 4 एससीसी 594 385

फुलमती धर्मदेव यादव और ए. एन. आर. बनामन्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [संजय करोल जे।]

आयुक्त के आदेश से, हमने 2013 की पहली अपील No.3487 में पारित आदेश को अलग कर दिया। अपील की अनुज्ञात है।

33. इसके परिणामस्वरूप, आयुक्त, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, भुज (कच्छ), गुजरात द्वारा W.C.F.C.No.08/10 में पारित आदेश को बहाल कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार जमा की गई राशि (शेष 80 प्रतिशत, 25 जून, 2014 के आदेश के अनुसार 2013 के सिविल आवेदन में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का 20 प्रतिशत जारी करने के बाद) और संचयी जमा राशि में रखी गई राशि, उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन में दावेदारों को तुरंत देय हो जाएगी। 34. दल अपना खर्च स्वयं उठाएंगे।

35. मध्यस्थ आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील अनुज्ञात ।

अंकित ज्ञान